dure. The Government of Andhra Pradesh has been requested to furnish clarifications in response to the Memorandum submitted by them. No Memorandum has been received from the other States in the wake of cyclone.

(e) It is primarily the responsibility of the State Governments concerned to undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities from the allocation under Calamity Relief Fund (CRF). The allocation made to Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa, Rajasthan and West Bengal under CRF during 1998-99 and the Central share is indicated below:

(Rs, in crore)

	Calamity Relief Fund	
	Allocation	Central share
Andhra Pradesh	137.73	103.30
Gujarat	154.83	116.12
Orissa	54.36	40.77
Rajasthan	198.56	148.92
West Bengal	56.92	42.69

The entire Central Share has been released to these States.

(f) The India Meteorological Department (IMD) Centre in Gujarat has been strengthened. The Govt, of Gujarat has prepared State Level and District Level Contingency Plans to deal with cyclones.

यूरिया की कीमत में वृद्धि से यूरिया की बिक्री और खपत पर प्रभाव

1740. श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरिया की कीमतों में वृद्धि की हैं,

(ख) यदि हां, तो इससे यूरिया की खपत और बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा ,

(ग) यूरिया की कीमतों में पिदली बार वृद्धि कब की गई थी, और

(घ) क्या इय मूल्य वृद्धि से यूरिया की खपत में गिरावट आने की आशंका हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क)दिनांक 29.1.1999 से यूरिया के अधिकतम मूल्य 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति मीटरी टन कर दिए गए हैं ।

(ख) और (घ) यूरिया के मूल्य में वृद्धि से संभवतया यूरिया की खपत और बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) दिनांक 21.2.1997 से यूरिया का अधिकतम मूल्य आखिरी बार 2760 रुपए से बढ़ाकर 3660 रुपये प्रति मीटरी टन हो गया । 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से 4160 रुपये प्रति मीटरी टन की मूल्य वृद्धि जो 1.6.98 से लागू हुई थी, दिनांक 13.6.1998 को वापिस ले ली गई।

औषधीय दृष्टि से मूल्यवान वानस्पतिक उद्यान

1741. **श्रीमती सरोज दुबे** :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधीय बाग लगवाकर वानस्पतिक उद्यान्नों के विकास के लिए कोई योजना बना रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के उद्योगों का विकास करने वालों को कोई विशेष सहायता या प्रोत्साहन देगी,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौंरा क्या हैं, और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय आठवीं योजना से ही 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से "औषधीय तथा सुगंधित पादवों का विकास" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा हैं । इस योजना के तहत 16 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जड़ी-बूटियों के बगीचों की स्थापना के लिए 75,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा इनकी देख-भाल के लिए 35,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता दी जा रही हैं । इसी प्रकार औषीधीय पौधों की नर्सरी की स्थापना के लिए एक लाख 35,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता दी जा रही हैं । यह योजना 1997-98 के दौरान जारी थी तथा इसे 1998-99 में भी चलाया जा रहा हैं । भारतीय

औषधि पद्धति वे होमियोपैथी विभाग भी औषधीय पौधों के विकास तथा खेती के लिए एक केन्द्रीय योजना क्रियान्वित कर रहा हैं जिसके तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी में उपयोग में लाये जाने वाले अभिज्ञात औषधीय पौधों की खेती के लिए जड़ी-बूटियों के बगीचों की स्थापना तथा विस्तार के लिए सहायता दी जा रही हैं । इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ क्षेत्र को शामिल करने के लिए 8.30 लाख रुपये तक का अनावर्ती अनुदान दिया जाता हैं । यह योजना 1997-98 के दौरान जारी रखी गई तथा इसे 1998-99 में भी चलाया जा रहा हैं ।

(ग) से (ड़) इन योजाओं के अंतर्गत भारतीय औषधि पद्धति तथा होमियोपैथी के विभिन्न कालेजों सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संगठनों के लिए सहायता उपलब्ध हैं ।

कृषि आधारित उद्योग के लिए राष्ट्रव्यापी योजना

1742. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना लागू करने जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा जो प्रारूपण के अंतिम चरणों में हैं, उसमें खाद्य एंव कृषि प्रसंस्करणा उद्योग की तेजी से विकास की परिकल्पना की गई हैं ताकि घरेलू और निर्यात बाजार हेतु मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सके ।

Effect of Shortage of Fertilizers of Wheat Crop

1743. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether shortage of DAP fertilizer in the distribution network has been reported;

(b) if so, the reasons therefor and the projected requirement for 1998-99 and actual availability till day; and

(c) the measures taken to ensure that wheat crop is not affected/damaged due to shortage or breakdown in supplies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Di Ammonium Phosphate (DAP) is a decontrolled fertilizer and Government of India does not control its distribution and movement. Against a projected requirement of 61.84 LMT of DAP during 1998-99, the actual availability till the middle of February, 1999 has been 64.44 LMT. Although the overall availability of this fertilizer was more than the projected requirement, localised shortages were reported from some North Indian States during October-November, 1998, mainly due to bunching of imports and sharp increase in the area of wheat cultivation.

(c) The measures taken to improve availability of DAP were priority berthing of DAP vessels at ports, speedy evacuation by rail from plants and ports, and priority import of 55,000 tonnes of DAP.

Decline in Crop Productivity

1744. SHRI SANTAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that crop productivity in some States are going down;

(b) if so, what steps are being taken to improve production in those States; and

(c) whether any special drive is being taken for the Sate of Orissa in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The crop productivity is generally maintaining an increasing trend in the country, though there are fluctuations over crops/States due to diverse agro-climatic conditions.

(b) In order to increase production and productivity of various crops, the Government is implementing crop